प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 43 अंक – 51 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 17 – 24 दिसम्बर 2018 मूल्य पांच रूपए

सरकार के जश्न से पूर्व विक्रमादित्य की आक्रामकता से फिर उलझे सियासी समीकरण

- संजय कुण्डु और प्रवीण गुप्ता पर बिना नाम लिये हमला
- जश्न से पहले उपलब्धियों पर मांगा श्वेत पत्र
- भारद्वाज और कपूर में तालमेल न होने से नहीं मिली बर्दियां
- महेन्द्र सिंह पर 113 4 करोड़ की बागवानी परियोजना तबाह करने का आरोप

शिमला/शैल। जयराम सरकार का 27 दिसम्बर को सत्ता में एक साल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर सरकारी स्तर पर जश्न मनाया जा रहा है और प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसी मौके पर कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ आरोपपत्र लाने जा रही है। सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल पर यदि निष्पक्षता से नजर डाली जाये तो यह सामने आता है कि अब तक सरकार और विपक्ष के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण ही चल रहे थे। इसी मैत्री का परिणाम रहा कि सरकार ने कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद दे ही दिया। भाजपा ने बतौर विपक्ष जो आरोपपत्र वीरभद्र सरकार के खिलाफ सौंपे थे उन पर कारवाई भी अब तक शून्य ही रही है। कांग्रेस शासन में भाजपा के जिन नेताओं के खिलाफ मामले बने थे उन्हे अब जयराम सरकार वापिस ले रही है। इस वापसी पर कांग्रेस लगभग खामोश चल रही है। बल्कि भाजपा ने अपने सचेतक और उपसचेतक को मन्त्री का दर्जा तथा उसी के समकक्ष अन्य सुविधायें दे दी हैं। विधानसभा में इस आश्य का विधेयक पारित करवाकर जयराम ने इस पर नियुक्ति भी कर दी है। लेकिन कांग्रेस इसमें ब्यानबाजी की रस्मी खिलाफत से आगे नही बढ़ी है जबकि यह विधेयक और इस पर की गयी नियुक्ति एकदम गलत है। यही नहीं इस विधानसभा सत्र से पूर्व वीरभद्र सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अभी जयराम का विरोध नही किया जाना चाहिये। उन्हे और मौका दिया जाना चाहिये। विधानसभा में उन्हें नही घेरेंगे और कांग्रेस ने सत्र में इस आश्वासन पर अमल भी किया।

लेकिन विधानसभा सत्र के बाद अब जिस तरह से वीरभद्र के बेटे शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने जयराम और उनकी सरकार पर हमला बोला है उससे यह सोचने पर विवश होना पड़ता है कि अचानक ऐसा क्या घट गया है कि जिसके कारण विक्रमादित्य के तेवर इतने तल्ख हो गये। इसमें सबसे पहले तो यही आता है कि इस दौरान पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आये हैं और इनमें भाजपा के अभेद्द गढ़ रहे मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसढ़ में कांग्रेस ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। इससे पूरे देश में हर कांग्रेसी उत्साहित है लेकिन इस उत्साह में सरकार पर रस्मी आक्रामकता तो समझ आती है लेकिन विक्रमादित्य का हमला तो रस्मअदायगी से कहीं आगे निकल गया है। जब उन्होंने यह कहा कि सरकार का एक प्रधान सचिव विजिलैन्स के कार्यालय में जाकर अधिकारियों पर कानून के दायरे से बाहर जाकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामले बनाने का दबाव डाल रहे हैं। विक्रमादित्य ने ऐसे अधिकारियों को सीधे -सीधे चेतावनी दी है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर ऐसे अधिकारियों को ''फटक-फटक'' कर देख लेंगे। समझा जा रहा है कि विक्रमादित्य का यह इशारा प्रधान सचिव विजिलैन्स संजय कुण्डु की ओर है। क्योंकि उन्हें जयराम दिल्ली से अपने कार्यालय में तैनाती देने के नाम पर लाये हैं और मुख्यमन्त्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के साथ प्रधान सचिव विजिलैन्स तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय में गठित गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गयी है। वीरभद्र के कार्यकाल में गुणवत्ता का कितना ध्यान रखा गया है इसका प्रमाण टाऊनहॉल के उद्घाटन समारोह में मिल चुका है और शायद इस गुणवत्ता पर संजय कुण्डु ने संवद्ध अधिकारियों से पूछा भी है।

संजय कुण्डु के बाद विक्रमादित्य ने प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधीक्षण अभियन्ता रहे प्रवीण गुप्ता की नियुक्ति पर भी गंभीर सवाल उठाया है। प्रवीण गुप्ता को जयराम सरकार ने पिछले दिनों पर्यावरण विभाग में अतिरिक्त निदेशक लगाने के साथ ही पर्यटन विभाग में एडीवी पोषित परियोजनाओं का प्रभारी भी बनाया है। विक्रमादित्य ने आरोप लगाया है कि प्रवीण गुप्ता एक कनिष्ठ अधिकारी हैं और ऐसी नियुक्तियों से वरिष्ठ अधिकारियों का मनोबल गिरता है। उन्होंने यह भी कहा कि नियुक्ति मुख्यमन्त्री के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण दी गयी है।

स्मरणीय है कि प्रवीण गुप्ता की पत्नी प्रदेश लोकसेवा आयोग की सदस्य है और जब वह पत्रकारिता में थी तब हॉलीलॉज से भी उनके अच्छे संबंध थे तथा अब इस सरकार से भी उनकी नजदीकीयां हैं। सत्ता से नजदीकीयों का लाभ हर सरकार में उठाया जाता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वीरभद्र के शासनकाल में उनके प्रधान निजी सचिव सुभाष आहलूवालिया की पत्नी मीरा वालिया की पहले शिक्षा नियामक आयोग और फिर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नियुक्ति रही है। बल्कि इस नियुक्ति

को प्रदेश उच्च न्यायायल में उसी दौरान चुनौती भी दे दी गयी थी और यह मामला अभी तक उच्च न्यायालय में लंबित चल रहा है।

इसी के साथ विक्रमादित्य ने जयराम सरकार द्वारा बाबा रामदेव को लीज़ पर भूमि देने के मामले में भी सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस ज़मीन की लीज़ राशी 28 करोड़ बनती थी उसे महज़ दो करोड़ बीस लाख दे दिया गया जबकि बाबा रामदेव की गिनती आज देश के पहले दस बड़े उद्योगपत्तियों में होती है। इसलिये उन्हें यह रियायत नही दी जानी चाहिये थी लेकिन कांग्रेस शासन में भी यही रियायत रामदेव को दी जा रही थी तब विक्रमादित्य इस पर खामोश थे। विक्रमादित्य ने जयराम सरकार पर एक लाख तबादले करने का आरोप लगाने के साथ ही यह भी कहा कि शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों में आपसी तालमेल न होने के कारण अब तक छात्रों को स्कूलों में बर्दी नही दी जा सकी है। दोनो विभागों के मन्त्रीयों में भी कोई तालमेल नही है। शिक्षा विभाग में घटे छात्रवृति घोटाले से लेकर बागवानी विभाग की 1134 करोड़ की परियोजना को भी तबाह कर दिये जाने का आरोप से पहले अपनी उपलब्धियों पर श्वेतपत्र जारी करने की भी मांग की है। कानून और व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विक्रमादित्य ने कसौली में नगर नियोजन विभाग की अधिकारी शैल बाला और शिलाई में जिन्दान की हत्या के मामले उठाते हुए सरकार द्वारा राजीव बिन्दल और किशन कपूर के मामले वापिस लिये जाने पर भी एतराज जताया।

विक्रमादित्य के तेवर काफी तल्ख रहे हैं और संजय कुण्डु तथा प्रवीण गुप्ता पर उनका निशाना साधना सीधे मुख्यमन्त्री पर हमला माना जा रहा है। लेकिन इस हमले का जबाव सरकार या भाजपा की ओर से न आना और भी कई सवाल खड़े कर देता है। बल्कि स्वयं मुख्यमन्त्री ने भी जो जबाव दिया है वह भी काफी कमज़ोर माना जा रहा है यह कहा जाता रहा है कि इस संद्धर्भ में मुख्यमन्त्री को उनके अधिकारियों द्वारा वांच्छित जानकारियां नही दी जा रही है। विक्रमादित्य की इस प्रैसवार्ता के बाद सियासी हल्कों में यह अटकलें तेज हो गयी हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में मण्डी से कांग्रेस का उम्मीदवार वीरभद्र परिवार का ही कोई सदस्य होगा और यह सदस्य विक्रमादित्य सिंह भी हो सकते हैं। क्योंकि विक्रमादित्य के बाद वीरभद्र सिंह ने भी ठियोग में जयराम सरकार पर हमला बोला है। मण्डी में जब सत्तपाल सत्ती ने रामस्वरूप शर्मा की पुन: प्रत्याशी बनाये जाने की घोषणा की थी तब उस पर पंडित सुखराम ने जिस तरह से इस घोषणा पर सवाल उठाया था उससे स्पष्ट हो जाता है कि मण्डी भाजपा के लिये कठिन होने जा रही है। इस परिदृश्य में यदि जयराम सरकार समय रहते न संभली तो वीरभद्र परिवार के बदलते तेवर उसके लिये खतरे के संकेत हो सकते हैं।

भाजपा और सरकार के लिये घातक होगी राहूल-प्रियंका पर अभद्र टिप्पणी

शिमला/शैल। कांग्रेस से ''आप'' और आप से भाजपा में पहुंचे डाक्टर रणवीर सिंह नेगी ने सोशल मीडिया में राहूल गांधी और प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी करके भाजपा के लिये प्रदेश में भयानक कठिनाई खड़ी कर दी है। आज तक सोशल मीडिया के मंच पर जिस तरह से राहूल और पूरे नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ अभद्रता परोसी जाती रही है उसी के कारण इन विधानसभा चुनावों में 2014 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले में भाजपा को 16% समर्थन का नुकसान उठाना पड़ा है। आज तक हिमाचल इस तरह की घटित हरकतों से बचा हुआ था। लेकिन आज नेगी जैसे अति उत्साहियों ने बैठे -बिठाये कांग्रेस को एक मुद्दा दे दिया है। नेगी की टिप्पणी पर उभरे रोष के परिणामस्वरूप युवा कांग्रेस, कांग्रेस की शिकायत पर प्रदेश के कई हिस्सों में पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है।

नेगी की टिप्पणी से मुस्लिम समुदाय में भी रोष के स्वर उभरे हैं। अब यह नेगी प्रकरण भाजपा और जयराम सरकार के लिये एक परीक्षा साबित होने जा रही है। इसमें यदि भाजपा नेगी को तुरन्त प्रभाव से बाहर का रास्ता नही दिखाती है तो यह माना जायेगा कि इस टिप्पणी को कहीं न कहीं पार्टी का समर्थन हासिल है। यही स्थिति सरकार के लिये होगी। यदि पुलिस इस मामले में तुरन्त प्रभाव से कारवाई नहीं करती है तो उससे भी यही सन्देश जायेगा कि इसमें सरकार की भी अपरोक्ष में सहमति है। अब इस पर सबकी निगाहें लगी हैं कि सरकार और पार्टी इसमें क्या कदम उठाते हैं। यह तय है कि यदि इसमें कोई ढील बरती गयी तो इसका चुनावों मे नुकसान उठाना पड़ेगा।

शैल समाचार के नियमित पाठक बनने हेतू
विज्ञापन देने के लिये इन नम्बरों पर संपर्क करें
कार्यालय दूरभाष – 0177 – 2805015, मो. 9418015015, मो. 9418069978, मो. 9418020312
ई मेल – shailsamachar@gmail.com, वेबसाईट – www.shailsamachar.co.in
पाठकों की प्रतिक्रियाओं को भी विशेष स्थान दिया जायेगा
– संपादक

NPS का मसला राज्यपाल के दरबार में, मिला केवल आश्वासन

शिमला/शैल। न्यू पैंशन स्कीम को समाप्त कर उसकी जगह पुरानी पैंशन बहाल करने की मांग का मसला राज्यपाल आचार्य देवव्रत के दरबार में भी पहुंच गया हैं। प्रदेश ही नहीं देश भर के कर्मचारी पुरानी पैंशन स्कीम की बहाली को लेकर आंदोलन पर हैं।

एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने राज्यपाल से कहा कि न्यू पैंशन स्कीम कर्मचारियों के बुढ़ापे के साथ धोखा है। संघ ने कहा कि 15 मई 2003 के बाद नियुक्त व नियमित हुए कर्मचारियों का जीवन निर्वाह होना मुश्किल में है।

संघ के सदस्यों ने यह भी मांग की कि केन्द्र सरकार व अन्य राज्य सरकारें जो एनपीएस के तहत लाभ अपने कर्मचारियों को दे रही हैं। प्रदेश सरकार अभी भी उन लाभों को देने में आना कानी कर रही है जिसमें सेवाकाल के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है तो उसे या उसके परिवार को पैंशन लाभ नहीं मिल रहे हैं। जबकि पुरानी पैंशन स्कीम में यह प्रावधान था।

महासंघ ने कहा कि ग्रेच्युटी के लाभ देने के लिए हिमाचल सरकार ने जो अधिसूचना 18 सितंबर 2017 को जारी की है उसमें भी कई खामियां है। मसलन जो कर्मचारी 15 मई 2003 से 18 सितंबर 2017 के बीच सेवानिवृत हुए हैं उन्हें यह डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्यूटी के लाभ से वंचित कर दिया है।

संघ ने कहा कि यह कर्मचारियों के साथ भेदवाव है और 18 सितंबर 2017 की अधिसूचना को पीड़ित कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को देखते हुए इसे संशोधित किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री की रैली के दौरान सभी स्वास्थ्य संस्थान रहेंगे हाई अलर्ट पर

धर्मशाला/शैल। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गुरदर्शन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लाभार्थी रैली के दृष्टिगत जिला के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान लोगों के भारी आवागमन को ध्यान में रखते हुए किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए सभी चिकित्सा अधिकारियों को सतर्क रहने तथा सामान्य चिकित्सा सुविधाओं को 24 घंटे सुनिश्चित बनाए रखने के निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान लोगों को राजेन्द्र प्रसाद मेडीकल कॉलेज टांडा तथा क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में सामान्य आपालकालीन चिकित्सा सेवाओं के अतिक्ति विशेष चिकित्सा सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी।

सीएमओ ने बताया कि सभा स्थल के नजदीक चार मेडीकल पोस्ट स्थापित की जायेंगी जिनमें एक डॉक्टर तथा पेरामेडीकल स्टॉफ के सदस्यों को तैनात किया जायेगा जबकि चिन्हित पार्किंग स्थलों पर भी लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु स्वास्थ्य विभाग की पांच मेडीकल टीमें गठित की गई हैं। गुप्ता ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में लोगों की जानकारी के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला के दूरभाष नम्बर 01892 – 222133, टांडा मेडीकल कालेज के दूरभाष नम्बर 01892 – 287187 इसके अलावा विशेष जिला के ज्वालामुखी अस्पताल के दूरभाष नम्बर 01970 – 222237, नूरपुर अस्पताल के दूरभाष नम्बर 01893 – 220036 तथा पालमपुर अस्पताल के दूरभाष नम्बर 01894 – 234101 पर सम्पर्क कर सकते हैं। इन सेवाओं के संचालन और सहयोग का जिम्मा मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश गुलेरी की निगरानी में रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य संबंधी किसी भी जानकारी के लिए डॉ. गुप्ता के मोबाईल नम्बर 94180 – 93360 तथा डॉ. गुलेरी के मोबाईल नम्बर 94184 – 79613 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
e-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

1.The Executive Engineer, Shimla, Division No.I, HPPWD, Shimla-3, H.P on behalf of Governor of H.P invites the online bids on item rate, in electronic tendering system, in 2 Cover System for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD Department.

Sr.No.	Name of Work	Estimated cost	EMD	Cost of Tender	Time Allowed
	Construction of roof over Balcony in Govt. Quarter Block A Type-3 Kasumpti (SH: Covering of balcony with expanded metal in Type-III Block G,H, old block 52 to 57, old block 58 to 67 and old block 100 to 105 Set No.52 to 61,64 to 75,77 to 79 & 81 to 83 under Parimahal Section)	576032/-	11600/-	350/-	60 days

2. Availability of Bid Document and mode of submission: The Bid document is available online and bid should be submitted in online mode on website **https://hptenders.gov.in.** Bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: **https://hptenders.gov.in.** Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender

3. Key Dates:

1. Date of Online Publication	28-12-2018 18.00 HRS
2. Document Download Start and End Date	28-12-2018 18.00 HRS upto 10-01-2019 16.00 HRS
3. Bid Submission Start and End Date	28-12-2018 18.00 HRS upto 10-01-2019 16.00HRS
4. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document	11-01-2019 upto 10.30HRS
5. Date of opening of Technical Bid	11-01-2019 11:00 HRS
6. Date of opening of Financial Bid	

4. TENDER DETAILS:
The Tender Documents shall be uploaded online in 2 Cover.
i). Cover 1: Shall contain scanned copies of all **" Technical documents/ Eligibility information."**
ii). Cover 2: Shall contain **"BOQ / Financial Bid",** where contractor will quote his offer for each item.
5. SUBMISSION OF ORIGINAL DOCUMENTS: The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security/Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in the **O/o Executive Engineer Shimla Division No-I HPPWD.**,Shimla-3 as specified in Key dates Sr. No. 3 on Tender Opening Date, failing which the bids will be declared non-responsive.
6. BID OPENING DETAILS: The Technical bids shall be opened on **11-01-2019 at 11:00 HRS** in the office of **Executive Engineer, Shimla HPPWD Shimla, H.P.** by the authorised officer. In their interest the tenderer are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 120 days after the deadline date for bid submission.
8. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.3671/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

एनपीसीसी के अध्यक्ष की राज्यपाल से भेंट

शिमला/शैल। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एनपीसीसी) के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक मनोहर कुमार ने राजभवन शिमला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाओं पर प्रस्तुति दी।

उन्होंने राज्यपाल को अवगत करवाया कि एनपीसीसी एक 'मिनी रतन – वर्ग – 1' निगम है जिसकी स्थापना 9 जनवरी, 1957 को देश के आर्थिक विकास के कोर सेक्टर जैसे सिंचाई और जल संसाधन, विद्युत और भारी उद्योग में आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने के लिए एक प्रमुख निर्माण कम्पनी के रूप में की गई। उन्होंने कहा कि एनपीसीसी थर्मल और जल विद्युत परियोजनाओं, नदी घाटी परियोजनाओं, औद्योगिक संरचनाओं, सड़कों पुलों, आवासीय अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं तथा भवन निर्माण परियोजना प्रबन्धन परामर्श सेवाओं के लिए गुणात्मक प्रबन्धन आवश्यकताओं में ISO 9001 – 2015 के मानकों का पालन करता है। अपने अस्तित्व के 58 वर्षो में निगम ने विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाओं में दूर – दराज एवं कठिन क्षेत्रों में परियोजनाओं की संकल्पना से परियोजना शुरू होने तक काम किया है। उन्होंने कहा कि निगम ने देश से बाहर भी कई परियोजनाओं का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं में भी कम्पनी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकती है।

राज्यपाल ने इस अवसर पर देश में सामाजिक – आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने के लिए एनपीसीसी के प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा गुणवत्ता नियंत्रण सेल और केन्द्रीय परियोजनाओं की निगरानी (विजिलेंस) संजय कुण्डू, राज्यपाल के सलाहकार डॉ. शशिकान्त शर्मा तथा एनपीसीसी के अधिकारीगण भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मानवीय चूक से होती हैं 80 प्रतिशत दुर्घटनायें: बी.के. अग्रवाल

शिमला/शैल। मुख्य सचिव बी. के. अग्रवाल की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने राज्य में सड़क सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित बनाई जा सके।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में प्रतिवर्ष औसतन 3000 दुर्घटनाएं घटती है। उन्होंने कहा कि इन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग, पुलिस, परिवहन विभाग तथा पथ परिवहन निगम को संयुक्त रूप से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 80 प्रतिशत दुर्घटनाएं मानवीय चूक के कारण होती हैं, जबकि 15 प्रतिशत दुर्घटनाएं सड़क की खराब हालत व प्रतिकुल मौसम के चलते होती हैं और 5 प्रतिशत दुर्घटनाएं तकनीकी कारणों से होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दो पहिया वाहनों की सर्वाधिक दुर्घटना के मामले सामने आए है, जबकि मोटर कार दुर्घटनाओं का प्रतिशत 30 से 36 प्रतिशत तथा बसों की दुर्घटनाओं का प्रतिशत 8 से 11 प्रतिशत है।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में 505 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए है, जो दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील है। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से इन स्थलों का दौरा कर निरीक्षण करने के आदेश दिए ताकि इन स्थलों का सुधार सुनिश्चित बनाया जा सके। उन्होंने पथ परिवहन विभाग को राज्य में पथ परिवहन निगम की बसों की दुर्घटनाओं के कारणों का तुलनात्मक अध्ययन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक माह के भीतर नीति बनाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्राईविंग लाईसेंस प्रक्रिया के दौरान नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ताकि पात्र लोगों को ड्राइविंग लाईसेंस मिल सके।

बी.के. अग्रवाल ने राज्य में स्थापित 270 ड्राईविंग स्कूलों में गुणवत्ता व सुधार सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में बायोमिट्रिक मशीन स्थापित करनी चाहिए तथा स्कूल का सारा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। उन्होंने इन स्कूलों का 15 – 20 दिनों के भीतर निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए ताकि इन संस्थानों में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य पुलिस द्वारा सितम्बर व अक्तूबर माह में यातायात उल्लघंन के 1643 मामले लाईसेंस रद्द करने के लिए पंजीकरण एवं लाईसेंस प्राधिकरण (आरएलए) को भेजे गए हैं। उन्होंने इन मामलों पर आरएलए को 15 दिनों के भीतर कारवाई करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने पुलिस तथा जिला प्रशासन को जिले के विभिन्न सम्पर्क मार्गो में दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने को भी कहा। उन्होंने निजी बसों के चालकों के लिए समय – समय पर लाईसेंस जांच करने व कार्यशालाएं आयोजित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों से लेकर हर माह बैठक आयोजित की जाएगी।

राफेल मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, सच्चाई की जीत:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राफेल मामले में सुनाया गया निर्णय कांग्रेस के मुॅह पर एक करारा तमाचा है, जिसने देश के लोगों को झूठ और मिथ्या प्रचार करके गुमराह किया है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात हरियाणा के रोहतक जिले में

एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम एवं कुशल नेतृत्व में हो रहे विकास से लोगों व राष्ट्र का ध्यान भटकाने के लिए हताशा में इस मुद्दे को हवा दी है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले पर झूठ बोलकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में ही नहीं डाला बल्कि देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक कृत्य के लिए देश के लोग कांग्रेस को कभी क्षमा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को देश से क्षमा मांगनी चाहिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राष्ट्र के हित में राफेल विमान खरीदने का बड़ा निर्णय लिया है। यह फैसला कांग्रेस व कुछ अन्य दलों को रास नही आ रहा है, जो इसमें गैर वांछित त्रुटियां ढुंढने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि यह डील को वर्ष 2007 में की गई थी पर केन्द्र में कांग्रेस के आठ सालों के शासन के दौरान इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय नही लिया गया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से प्रश्न किया कि क्या यह देरी इस वजह से हुई कि कांग्रेस सरकार इस डील में बिचोलियों के माध्यम से कमीशन प्राप्त नही कर पाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राफेल डील पर केवल राजनीतिक हितों को साधने तथा लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए झूठ का सहारा ले रही है जिसके लिए देश के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राफेल डील पर केन्द्र सरकार को बदनाम कर रहे है, लेकिन अब उनके आधारहीन आरापों पर उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस, विशेषकर राहुल गांधी के मुॅह पर एक करारा तमाचा है तथा उन्हें इससे सबक लेना चाहिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राफेल डील पर दुष्प्रचार करके देश के सम्मान को ठेस पहुंचाई है तथा आगामी लोकसभा चुनावों में देश के लोग कांग्रेस पार्टी को माकूल जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के साढ़े चार साल के शासनकाल में कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान सरकार के खिलाफ एक के बाद एक कई मुद्दे उठाने की कोशिश की है, परन्तु वे हमेशा नाकामयाब साबित हुए है तथा देश के लोग इनके गलत इरादों को भलीभांति समझते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व नेता के रूप में उभरे हैं तथा उनकी छवि से कांग्रेस पार्टी परेशान है तथा इसलिए वह झूठ का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को आज भी बोफोर्स का मामला याद है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आधारहीन ब्यानबाजी करने पर चेताया।

बैंक ऋण देने में दिखाएं उदारता:के.के. सरोच

शिमला/शैल। अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा के.के सरोच ने जिला के बैंकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लोगों को ऋण देने में उदारता दिखाने को कहा है। उन्होंने बैंको से सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत जनहित के कार्यो में सहयोग का

आग्रह किया। सरोच उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित कांगड़ा जिला के बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की सितम्बर, 2018 तिमाही बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

अतिरिक्त उपायुक्त ने जिला कांगड़ा के सभी बैंकों को तय समयावधि में अपने निर्धारित लक्ष्य पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसानों, बागवानों तथा जरूरतमंदों की सहायता में बैंक जिला प्रशासन का सक्रिय रूप से सहयोग करें। इस पर बैंक अधिकारियों ने उन्हें संबंधित संस्थानों की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि स्वर ग्रोवर ने अपने सम्बोधन में बैंकों को अधिक से अधिक वित्तीय जागरूकता कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को बैंको द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी हासिल हो सके। उन्होंने बैंको को ऋण जमा अनुपात, जो इस समय 23.29 प्रतिशत है में सुधार लाने के दिशा – निर्देश दिए।

बैठक में पंजाब नैशनल बैंक के उपमंडल प्रमुख प्रतीक श्रीवास्तव ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि कांगड़ा जिले के बैंकों ने सितम्बर तिमाही ऋण योजना 2018 – 19 के अंतर्गत 1802 करोड़ रुपये के एवज में 1717 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न बैंकों के पास लोगों के 25053.78 करोड़ रुपये जमा हैं तथा बैंकों ने लोगों को सितम्बर, 2018 की अवधि में 5834.71 करोड़ रुपये तक के ऋण वितरित किए हैं।

69 करोड़ की जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत शिमला शहर को 24 घण्टे होगा पानी उपलब्ध

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सुन्नी क्षेत्र के चाबा में शिमला शहर के लिए शिमला उठाऊ जलापूर्ति योजना के संवर्धन की आधारशिला रखी। यह जलापूर्ति योजना 69 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होगी और शिमला शहर के लिए प्रतिदिन 10 मिलियन लीटर अतिरिक्त जल प्रदान करेगी।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना शिमला शहर के लोगों को 24 घण्टे जलापूर्ति सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि योजना अगले वर्ष अप्रैल माह तक पूरी की जाएगी, जिससे शिमला क्षेत्र में जल की समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में पेयजल योजनाओं पर 275 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 90 प्रतिशत घरों को पेयजल आपूर्ति प्रदान की जा रही है, जो राष्ट्रीय औसत 43.5 प्रतिशत से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 4751 करोड़ रुपये की जल संग्रहण परियोजना प्रस्तावित की थी, जिसकी केन्द्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। यह परियोजना किसानों की आय को दोगुणा करने की दिशा में कारगर सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने लगभग एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश का चहुंमुखी व सन्तुलित विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने राज्य के कुल 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 62 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि दौरे का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक भाग के लोगों की विकासात्मक आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के बारे में जानकारी हासिल करना तथा उनका समाधान करना है। उन्होंने कहा कि ठीक एक वर्ष पहले 18 दिसम्बर, 2017 को राज्य के लोगों ने वर्तमान सरकार के पक्ष में अपना फैसला दिया था।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार का पहला ही निर्णय वृद्धजनों के कल्याण पर लक्षित था। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के

लिए बिना आय सीमा के आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया, जो राज्य सरकार का बुजुर्गो के प्रति सम्मान को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि सुन्नी तथा तत्तापानी क्षेत्र में जल क्रीड़ाओं की दृष्टि से काफी सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सुन्नी – तत्तापानी – करसोग – जंजैहली – शिकारी माता को पर्यटन सर्किट की दृष्टि से विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सुन्नी बस अड्डे का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा।

जय राम ठाकुर ने गौडु – पलघार सड़क तथा घैणी – तबोग सड़क के लिए 10 – 10 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न सम्पर्क सड़कों के लिए 23 लाख रुपये की घोषणा भी की। उन्होंने सुन्नी में खण्ड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय की घोषणा की और यह भी घोषणा की कि एसडीएम ग्रामीण सप्ताह में दो दिन सुन्नी में बैठेंगे।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक सादी पृष्ठभूमि से सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति आज राज्य का मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग एक वर्ष के दौरान अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के 2375 पदों को भरा गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सुन्नी को देश का प्रमुख जलक्रीड़ा गन्तव्य विकसित करने का आग्रह किया।

शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लिए 9000 करोड़ रुपये की केन्द्रीय परियोजनाएं प्राप्त करने में कामयाब रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश के पात्र परिवारों को 8 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं।

शिमला ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने उनके निर्वाचन सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए आशा जाहीर की कि क्षेत्र को वर्तमान राज्य सरकार से विकास के मामले में उचित संस्तुति प्राप्त होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से क्षेत्र में स्वास्थ्य अधोसंरचना मजबूत करने का भी आग्रह किया।

क्षेत्र से भाजपा नेता डॉ. प्रमोद शर्मा ने मुख्यमंत्री से सुन्नी में एसडीओ कार्यालय खोलने का भी आग्रह किया।

पेंशनरों की उचित मांगों पर विचार करेगी सरकार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अखिल भारतीय पेंशनर दिवस के अवसर पर पेंशनर कल्याण संघ द्वारा मण्डी जिला के सुन्दरनगर में आयोजित राज्य स्तरीय पेंशनर दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार पेंशनरों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, क्योंकि उन्होंने राज्य के विकास के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने सेवाकाल के दौरान पेंशनधारकों ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान

दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने में प्रमुख भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत होने के बाद भी सेवानिवृत कर्मचारी सरकार को राज्य के विकास के लिए नीतियों व कार्यक्रम को तैयार करने में सक्रिय योगदान देते हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सभी जायज मांगों को पूरा किया गया है।

स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री से पेंशनरों की लम्बे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने का आग्रह किया।

इस अवसर पर राज्य पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष एचआर वशिष्ठ ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए संघ की विभिन्न मांगों को उनके समक्ष रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री से पेंशनरों के लिए 5 – 10 – 15 के मानदण्ड को हटाने का आग्रह किया।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री को एएपीआई चौरीटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा डॉ. चन्द्र एम. कपासी ने मुख्यमंत्री को 14,38,400 रुपये का चेक भेंट किया। पेंशन कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1.25 लाख रुपये का चेक भेंट किया। विभिन्न संघों तथा व्यक्तियों ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष में भेंट प्रदान की।

विश्व एक व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं।।..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

किसान की कर्ज माफी पर सवाल क्यों

अभी हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने वायदा किया था कि यदि उसकी सरकार बन जायेगी तो वह सत्ता संभालते ही दस दिन के भीतर यहां के किसानों के दो लाख तक के कर्जे माफ कर देगी। चुनाव परिणाम आने पर तीन राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसकी सरकारें बन गयी और इन राज्यों के मुख्यमन्त्रीयों ने सबसे पहला काम कर्ज माफी का किया। इस कर्ज माफी को लेकर कई हल्कों में एतराज के स्वर भी सामने आये हैं। इस तरह की कर्ज माफी को सत्ता की सीढ़ी करार दिया जाने लगा है। इससे जीडीपी पर कुप्रभाव पड़ेगा यह तर्क भी सामने आया है कुल मिलाकर सारे गैर कांग्रेसी दलों ने इस कर्ज माफी का समर्थन नही किया है। इन दलों की पीड़ा समझी जा सकती है क्योंकि आज भी देश की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। इसी जनसंख्या से आने वाला किसान कर्ज के कारण आत्म हत्यायें कर रहा है यह कड़वा सच भी सबके सामने आ चुका है। किसान की आय 2022 तक दोगुनी हो जायेगी केन्द्र के इस आश्वासन के बावजूद आज का किसान अपनी फसले सड़क पर फैंकने के लिये विवश हो गया है। जब प्याज सड़कों पर फैंका गया तब सरकार ने उसके लिये मुआवज़े की घोषणा की। देश के हर कोने से आये किसानों ने दिल्ली में कितना लम्बा प्रदर्शन किया यह भी देश देख चुका है। हर तरह का खाद्यान खेत से ही पैदा होता है यह एक ध्रुव सत्य है। खेत का कोई विकल्प नही है और न ही हो सकता है यह एक सच्चाई है और सदैव बनी रहेगी। इस सच्चाई के कारण किसान को ''अन्नदाता'' की संज्ञा दी गयी है।

इस परिप्रेक्ष में जब किसान की स्थिति का आंकलन किया जाता है और उसकी आत्महत्याओं का सच सामने आता है तो यह सोचने पर विवश होना पड़ता है कि ऐसा हो क्यों हो रहा है और इस स्थिति से बाहर कैसे आया जा सकता है। इसमें सबसे पहले यही आता है कि इन आत्महत्याओं को कैसे रोका जाये इसके लिये तत्काल उपाय सीमान्त और छोटे किसान के कर्ज माफी के अतिरिक्त और कुछ नही हो सकता। इसलिये यह कर्ज माफी एकदम व्यवहारिक और अपरिहार्य कदम हो जाता है। इसका विरोध एकदम गलत है। हां इसी के साथ यह प्रयास भी साथ ही शुरू हो जाना चाहिये कि भविष्य में किसान को कृशि ऋण के कारण आत्महत्या करने की नौबत न आये। यहां यह उल्लेख करना भी प्रसांगिक होगा कि देश में सबसे पहले किसान के कर्जे माफ करने का कदम 1990 में उठाया गया था। जब 1989 में भाजपा के सहयोग के साथ केन्द्र में वीपी सिंह की सरकार बनी थी और 1990 में विधानसभाओं के चुनाव भी इसी तालमेल के साथ लड़े गये थे। तब स्व. चौधरी देवी लाल ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की थी और उस पर अमल किया था। आज जो लोग इसे कांग्रेस का सत्ता प्राप्ति का शॉर्टकट करार दे रहे हैं उन्हे 1989 और 1990 को याद रखना आवश्यक है। यह सही है कि कर्ज माफी इस समस्या का कोई स्थायी हल नहीं हो सकता क्योंकि यह कर्जमाफी अन्ततः आम आदमी पर ही भारी पड़ती है।

इस कर्ज माफी का स्थायी हल खोजने के लिये आवश्यक है कि यह तय किया जाये कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। आज जो आंकड़े सामने हैं उनके अनुसार देश में बेरोज़गारी हर वर्ष 9% की दर से बढ़ रही है। आंकडे यह भी बताते हैं कि पिछले तीन वर्षो में निवेश लगातार कम हुआ है। यह निवेश कम होने के साथ ही एनपीए का आंकड़ा भी बढ़ा है। 31 मार्च 2018 को यह एनपीए 12.5 लाख करोड़ हो गया था और देश के अनिल अंबानी जैसे उद्योग घराने पर भी दो लाख करोड़ का कर्ज है। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहूल चौकसी जैसे बड़े-बड़े एनपीए वाले लोगों की आत्महत्या की खबर कभी नहीं आती है क्योंकि यह लोग एनपीए लेकर विदेश चले जाते हैं। उनके कर्जे को एनपीए का नाम दे दिया जाता है। लेकिन किसान के साथ ऐसा नही होता। बैंक कर्ज वसूली के लिये उसके सिर पर खड़ा रहता है और फिर मज़बूर होकर वह आत्महत्या का रूख करता है। इसलिये यह समझना और मानना आवश्यक है कि कृषि को जबतक उद्योग से ऊपर का दर्जा नही दिया जायेगा तब तक स्थिति में सुधार हो पाना कठिन होगा। कृषि को उद्योग से ऊपर का दर्जा इसलिये चाहिये क्योंकि रोज़गार के जितने अवसर खेत पैदा करता है उतने उद्योग से नहीं। किसान का पूरा परिवार खेत में काम करता है लेकिन उसकी विडम्बना यह है कि उसे अपनी उपज की पूरी कीमत नही मिलती है। वह अपनी ऊपज की कीमत खुद तय नहीं कर पाता। उसके पास यह विकल्प नहीं होता कि यदि उसे पूरा दाम नहीं मिल रहा है तो वह उस ऊपज को अपने पास जमा करके रख ले क्योंकि उसके पास कोल्ड स्टोर की सुविधा नही है न ही उसके पास ऐसा कोई विकल्प रहता है कि उसकी उपज की प्रौसेसिंग से वह कुछ और तैयार कर सके। इसमें सबसे बड़ी हैरानी तो इस बात ही है कि आज तक किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में यह नहीं आता कि वह अपने चुनावक्षेत्र में इतने कोल्डस्टोर बनवा देगा और स्थानीय उपज पर आधारित कोई उद्योग इकाई वहां पर सहकारी क्षेत्र में लगा देगा। जब तक किसान के लिये यह सुविधायें उपलब्ध नही होगी उसे कर्ज से मुक्ति दिला पाना आसान नही होगा। आज हर सांसद और विधायक को क्षेत्रिय विकास निधि मिलती है लेकिन इनमें से कभी भी किसी ने इस तरीके से इस पर विचार नही किया। आज हर सांसद/विधायक अपने -अपने क्षेत्र की उपज के आधार पर कोल्ड स्टोर और प्रसंस्करण इकाईयां लगाने की बात शुरू करे दे तो निश्चित रूप से किसान और देश की स्थिति बदल जायेगी। गांवों में अच्छे रोज़गार के साधन उपलब्ध रहेंगे और शहरों की ओर पलायन रूक जायेगा।

अब राम के वन गमन पथ पर पंगा, मंत्रालय और एडवाइजरी कमेटी आमने-सामने

गौतम चौधरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक राम सर्किक का विकास है। यह भारत के लिए ही नहीं दुनिया भर में बसे हिन्दुओं के लिए धार्मिक आस्था की बात है। भारतीय राष्ट्रवाद और इस देश के लिए बेहद अच्छी योजना नरेन्द्र भाई की सरकार लेकर आ रहे हैं लेकिन इस योजना के साथ जो छेड़-छाड़ की जा रह है वह हिन्दुओं के आस्था पर प्रहार से कम नहीं है। विगत दिनों हमारे प्रधानमंत्री नेपाल के प्रवास पर गए थे। वहां उन्होंने माता जानकी के जनकपुर स्थित मंदिर का भी दर्शन किया। जानकी मंदिर में गूंजती घंटी प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल में होने की गवाही दे रही थी। सियाराममय माहौल में रामायण सर्किट की चर्चा भी बेहद स्वभाविक था।

आपको बता दें कि साल 2016 में भारत सरकार ने रामायण सर्किट की घोषणा की थी। दो साल बीत गए हैं लेकिन इस सर्किट पर अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। इस मामले पर अपने दूरदर्शन के लिए रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ट पत्रकार अमिताभ बताते हैं कि सरकार ने राम सर्किट निर्माण के लिए बाकायदा एक एक कमीटी बनाई है। उसके अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विश्व हिन्दू परिषद् से जुड़े विद्वान, जिन्होंने भगवान राम की यात्रा पर आधिकारिक किताब लिखी है, डॉ. रामावतार को बनाया है। उस समिति में वैष्णव संत एवं कथावाचक आदरणीय विजय कौशल जी महाराज को भी रखा गया है लेकिन मंत्रालय, मंत्री और सचिवालय की अकर्मण्यता के कारण दो साल में इस एडवाजरी कमेटी की मात्र दो बार बैठक हुई। उस बैठक में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया।

मसलन इस महत्वपूर्ण विषय में डॉ. रामावतार शर्मा ने बताया दो साल में दो बैठक हुई है, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, दफ्तर, स्टाफ और मंत्रालय का पास तक नहीं है। उन्होंने बताया कि राम वन गमन के मार्ग में मंत्रालय द्वारा संशोधन कर दिया गया है। डॉ. शर्मा का आरोप है कि यह अराध्य भगवान से जुड़े करोड़ों हिन्दुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। डॉ. शर्मा ने बताया कि जो गलती हो गयी है वो दुबारा नहीं हो, यही कोशिश है, रामायण सर्किट में गलती से एक वैसा स्थान भी शामिल हो गया है, जहाँ राम जी कभी गए ही नहीं। शर्मा इतने क्षुब्ध हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया, अब राम जी ही जाने कैसे होगा राम जी का काम। दरअसल, ये बात शर्मा जी को मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था, शर्मा जी आप परेशान मत हों काम राम जी ही कर लेंगे।

आज जो लोग देश को चला रहे हैं उनकी राजनीति के केन्द्र में भगवान श्री राम का होना बेहद जरूरी हैं। दरअसल, इन लोगों की भगवान श्री राम पर आस्था कितनी है यह तो पता नहीं लेकिन भगवान इन्हें वोटबैंक जरूर दिख रहे हैं। इस बात की चर्चा जब शर्मा ने संत विजय कौशल जी महाराज के समक्ष किए तो उन्होंने भी खिन्नता प्रगट की और कहा कि ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यद्यपि जब रामायण सर्किट का गठन हुआ था, तब सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव था। उस चुनाव के लिए भाजपा को यह जरूरी लगा लेकिन बाद में वे सारे के सारे वायदे कमजोर पड़ते चले गए।

भगवान राम की जन्म भूमि तो राजनीति का अखाड़ा बन ही गया है। अब हमारी राजनीति के आदर्श भगवान श्रीराम का वन गमन पाथ भी राजनीति और व्यापार की भेंट चढ़ता दिख रहा है। अब आपको यह भी बता दें कि यह सर्किट आखिर है क्या?

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने साल 2016 में रामायण सर्किट का गठन किया। एक अध्यक्ष समेत कुल पांच सदस्यों वाली रामायण सर्किट को धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण योजना करार दिया गया था। रामायण सर्किट के कार्यक्षेत्र में नेपाल से श्रीलंका तक के महत्वपूर्ण स्थल निर्धारित किये गये थे, श्रीराम से सम्बद्ध मान्यता और आस्था वाले स्थलों के चयन और उनके विकास की रुपरेखा तैयार करने की जवाबदेही भी रामायण सर्किट के जिम्मे लगाई गयी। ठीक उसी समय भारत सरकार के राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय ने भी अपनी रामभक्ति जाहिर की। राम वनगमन पथ के निर्माण और विस्तार की योजना मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित की गयी। श्रीराम के वनगमन पथ और महत्वपूर्ण स्थल चयन के आधार भी बेहद दिलचस्प है। इस संदर्भ में डॉ. शर्मा बताते हैं कि रामायण सर्किट और राम वनगमन पथ, योजना के घोषणा के समय को ठीक से देखा जाए तो सरकार की मंशा को समझना बेहद आसान होगा। दरअसल, इन योजनाओं की घोषणा जिस वक्त की गयी वो वक्त यूपी के लिए चुनावी वक्त था। सरकारी सर्वेक्षण के बिना शुरू हुए इन योजनाओं को पूरा करने की कोई भी डेड लाईन फिलहाल तय नहीं है। मतलब बेहद साफ है सियासत की रामनीति कभी भी करवट ले सकती है।

राम सर्किट एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. रामावतार शर्मा का आरोप है कि मंत्रालय ने भगवान राम के वन गमन मार्ग में श्रृंगमेरपुर, केवट द्वारा पार उतारे जाने के बाद भगवान जहां रात्रि को विश्राम किया टाटासरुआ, त्रिवेणी संगम, भारद्वाज आश्रम, अक्षयवट, यमुना पार करने का स्थान, कुमारद्वय, वाल्मीकी आश्रम, केवट ने जहां से भारत जी को चित्रकूट के दर्शन कराए, ये सारे स्थान हटा दिए हैं। डॉ. शर्मा ने बताया कि सरकार से आशाएं थी वह ध्वस्त हो गयी है। यदि इन स्थानों को भगवान राम वन गमन पथ से हटा देगी तो हमारी पौराणिक आस्था खंडित होगी और फिर इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है यह राम जी जाने लेकिन मुझे तो मोदी सरकार से उम्मीद थी वह अब समाप्त हो गयी है।

अब जब 2019 का आम चुनाव निकट आया तो एक बार फिर से सरकार इस योजना को लेकर मैदान में है। कहा जा रहा है कि इस योजना से करोड़ों युवाओं को नौकरी मिलेगी। कहा यहां तक जा रहा है कि इस योजना को लेकर खुद प्रधानमंत्री चिंता कर रहे हैं। अब इसे स्वदेश दर्शन योजना के तहत केन्द्र सरकार देशभर में टूरिज्म को बढ़ावा देगी।

कहा जा रहा है कि सरकार रामायण सर्किट के विकास के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है। लेकिन विभाग और एडवाइज़री कमेटी के बीच जो आस्था का अंतरविरोध है वह अभी भी यथावत है। इसे जब तक दूर नहीं किया जाता तब तक इस पूरी योजना को परवान चढ़ाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा।

दस घंटे के भीतर कर्ज माफी के एलान का मतलब....

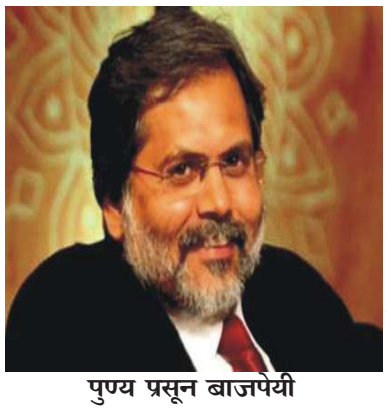

पुण्य प्रसून बाजपेयी

ना मंत्रियों का शपथ ग्रहण ना कैबिनेट की बैठक। सत्ता बदली और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही किसानों की कर्ज माफी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिये। ये वाकई पहली बार है कि राजनीति ने इक्नॉमी को हडप लिया या फिर राजनीतिक अर्थशास्त्र ही भारत का सच्च हो चला है। राजनीतिक सत्ता के लिये देश की इक्नॉमी से जो खिलवाड़ बीते चार बरस में किया गया उसने विपक्ष को नये संकेत यही दे दिये कि इक्नॉमी संभलती रहेगी पहले सत्ता पाने और फिर संभालने के हालात पैदा करना जरुरी है। हुआ भी यही कर्ज में डूबे मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता पन्द्रह बरस बाद कांग्रेस को मिली तो बिना लाग लपेट दस दिनो में कर्ज माफी के एलान को दस घंटे के भीतर कर दिखाया और वह सारे पारंपरिक सवाल हवा हवाई हो गये कि राज्य का बजट इसकी इजाजत देता है कि नहीं । दरअसल, मोदी सत्ता ने जिस तरह सरकार चलायी है उसमें कोई सामान्यजन भी आंखे बंद कर कह सकता है कि नोटबंदी आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक फैसला था। जीएसटी जिस तरह लागू किया गया वह आर्थिक नहीं राजनीतिक फैसला है। रिजर्व बैंक में जमा तीन लाख करोड़ रुपया बाजार में लगाने के लिये मांग करना भी आर्थिक नहीं राजनीतिक जरुरत है। पहले दो फैसलों ने देश की आर्थिक कमर को तोडा तो रिजर्व बैंक के फैसले ने ढहते इकनॉमी का खुला इजहार किया। फिर बकायदा नोटबंदी और जीएसटी के वक्त मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविन्द सुब्रमणयम ने जब पद छोडा तो बकायदा किताब 'ऑफ काउसिंल, द चैलेंज ऑफ मोदी-जेटली इक्नॉमी', लिखकर दुनिया को बताया कि नोटबंदी का फैसला आर्थिक विकास के लिये कितना घातक था। और जीएसटी ने इक्नॉमी को कैसे उलझा दिया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुरामराजन का मानना है कि किसानों की कर्ज माफी से किसानो के संकट दूर नहीं होगें। और संयोग से जिस दिन रघुरामराजन ये कह रहे थे उसी दिन मध्यप्रदेश में कमलनाथ तो छत्तीसगढ में भूपेश बधेल सीएम पद की शपथ लेते ही कर्ज माफी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो सवाल तीन है, पहला- क्या राजनीति और इक्नॉमी की लकीर मिट चुकी है। दूसरा- क्या 1991 की लिबरल इक्नॉमी की उम्र अब पूरी हो चुकी है। तीसरा- क्या ग्रामीण भारत के मुश्किल हालात अब मुख्यधारा की राजनीति को चलाने की स्थिति में आ गये है। ये तीनों सवाल ही 2019 की राजनीतिक बिसात कुछ इस तरह बिछा रहे हैं जिसमें देश अब पिछे मुडकर देखने की स्थिति में नहीं है । और इस बिसात पर सिर्फ 1991 के आर्थिक सुधार ही नहीं बल्कि मंडल-मण्डल से निकले क्षत्रपों की राजनीति भी सिमट रही है। पर कैसे राजनीति और अर्थव्यवस्था की लकीर मिटी है और वैकल्पिक राजनीतिक अर्थसास्त्र कीा दिशा में भारत बढ रहा है ये कांग्रेस के जरीये बाखूबी समझा जा सकता है । कांग्रेस मोदी सत्ता के कारपोरेट प्रेम को राजनीतिक मुद्दा बनाती है । किसानों की कर्ज माफी और छोटे और मझौले उद्योगों के लिये जमीन बढ़ाने और मजदूरों के हितो के सवाल को मनरेगा से आगे देखने का प्रयास कर रही है। जबकि इन आधारों का विरोध मनमोहन इक्नॉमिक्स ने किया, लेकिन अब कांग्रेस कृषि अर्थशास्त्र को समझ रही है लेकिन उसके पोस्टर ब्वाय और कोई नही मनमोहन सिंह ही है।

यानी तीन राज्यो में जीत के बाद करवट लेती राजनीति को एक साथ कई स्तर पर देश की राजनीति को नायाब प्रयोग करने की इजाज़त दी है, या कहे खुद को बदलने की सोच पैदा की है। पहले स्तर पर कांग्रेस रोजगार के साथ ग्रोथ को अपनाने की दिशा में बढ़ना चाह रही है। क्योंकि लिबरल इक्नॉमी के ढांचे को मोदी सत्ता ने जिस तरह अपनाया उसमें 'ग्रोथ विदाउट जाब' वाले हालात बन गये। दूसरे स्तर पर विपक्ष की राजनीति के केन्द्र में कांग्रेस जिस तरह आ खड़ी हुई उसमें क्षत्रपों के सामने ये सवाल पैदा हो चुका है कि वह बीजेपी विरोध करते हुये भी बाजी जीत नहीं सकते। उन्हे कांग्रेस के साथ खड़ा होना ही होगा और तीसरे स्तर पर हालात ऐसे बने हैं कि तमाम अंतर्विरोध को समेटे एनडीए था जिसकी जरुरत सत्ता थी पर अब यूपीए बन रहा है जिसकी जरुर सत्ता से ज्यादा खुद की राजनीतिक जमीन को बचाना है। ये नजारा तीन राज्यो में कांग्रेस के शपथ ग्रहण के दौरान विपक्ष की एक बस में सवार होने से भी उभरा और मायावती, अखिलेश और ममता के ना आने से भी उभरा।

दरअसल, मोदी-शाह की बीजेपी ममता बर क्षत्रपो की राजनीतिक जमीन को सत्ता की मलाई और जांच एंजेसियो की धमकी के जरीये तरह खत्म करना शुरु किया तो क्षत्रपो के सामने संकट है कि वह बीजेपी के साथ जा नहीं सकते और कांग्रेस को अनदेखा कर नहीं सकते। इस कड़ी में समझना ये भी होगा कि कांग्रेस का मोदी सत्ता या ये कहें बीजेपी विरोध पर ही तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत का जनादेश है। इस जीत के भीतर मुस्लिम वोट बैंक का खामोश दर्द भी छुपा है। कर्ज माफी से ओबीसी व एससी-एसटी समुदाय की राजत भी छुपी है और राजस्थान में जाटो का पूर्ण रुप से कांग्रेस के साथ आना भी छुपा है। इसी कैनवस को अगर 2019 की बिसात पर परखे तो क्षत्रपो के सामने ये संकट तो है कि वह कैसे कांग्रेस के साथ कांग्रेस की शर्तो पर नहीं जायेगें। क्योंकि कांग्रेस जब मोदी सत्ता के विरोध को जनादेश में अपने अनुकुल बदलने में सफल हो रही है तो फिर क्षत्रपो के सामने ये चुनौती भी है कि अगर वह कांग्रेस के खिलाफ रहते हैं तो चाहे अनचाहे माना यही जायेगा कि वह बीजेपी के साथ है। उस हालात में मुस्लिम, दलित, जाट या कर्ज माफी से लाभ पाने वाला तबका क्षत्रपो का साथ क्यों देगा। यानी तमाम विपक्षी दलों की जनवरी में होने वाली अगली बैठक में ममता, माया और अखिलेश भी नजर आयेंगे। अब बीजेपी के सामने चुनौती है कि वह कैसे अपने सहयोगियों को साथ रखे और कैसे लिबरल इक्नॉमी का रास्ता छोड़ वैकल्पिक आर्थिक मॉडल को लागू करने के लिये बढ़े। यानी 2019 का राजनीतिक अर्थशास्त्र अब इबारत पर साफ साफ लिखी जा रही है कि कॉरपोरेट को मिलने वाली सुविधा या रियायत अब ग्रमीण भारत की तरफ मुडेगी। यानी अब ये नहीं चलेगा कि उर्जित पटेल ने रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया तो शेयर बाजार सेंसेक्स को कॉरपोरेट ने राजनीतिक तौर पर शक्तिकांत दास के गवर्नर बनते ही संभाल लिया क्योंकि वह मोदी सत्ता के इशारे पर चल निकले। और देश को ये मैसेज दे दिया गया कि सरकार की इक्नॉमिक सोच की पटरी ठीक है उर्जित पटेल ही पटरी पर नहीं थे।

हिमाचल में आयुर्वेद को नई ऊंचाईयों तक ले जाने का राज्य सरकार का संकल्प

राज्य में विशाल हर्बल संपदा विद्यमान है, और प्रदेश सरकार पारंपरिक भारतीय चिकित्सा परिसंपतियों के समुचित दोहन के प्रति वचनबद्ध है। प्राचीन काल से ही भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपेथी की स्वास्थ्य उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह ऐसी उपचार पद्धति है जो रोग को हमेशा के लिए जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखती है।

प्रदेश में 34 आयुर्वेदिक अस्पताल, 1175 आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र 14 होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र, 3 युनानी स्वास्थ्य केंद्र, 4 अमाची स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से लोगों को उपचार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। विभिन्न आयुर्वेदिक अस्पतालों में 17 स्थानों पर पंचकर्मा विशेषज्ञ सेवाएं तथा 9 क्षारसूत्र इकाईयां स्थापित की गई हैं। आयुर्वेद विशेषज्ञ जैसे पंचकर्म क्षारसुत्र उपचारात्मक योग इत्यादि सेवाएं भी आयुर्वेदिक असपतालों में प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के तीन विकास खण्डों ठियोग, करसोग तथा कसौली में एनीमिया रोकथाम कार्यक्रम की घोषणा की गई है जिस पर एक करोड़ 27 लाख रुपये की धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है। यह राशि आयुष मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा रही है। आयुर्वेद निदेशालय में केन्द्रीय सहायता से एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना की गई है जिससे केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं को समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जा सके तथा युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हों। इस प्रकार की इकाईयां जिला स्तर पर भी स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केन्द्र को भेजा था जिसे मंत्रालय ने सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की है।

केन्द्र सरकार को तीन राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसियां तथा एक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए चार करोड़ की केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिस पर आयुष मंत्रालय ने अपनी सहमति प्रदान की है। यह राशि फार्मेसियों के लिए नई मशीनों का क्रय करने तथा इन हाउस गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित के अलावा श्रमशक्ति बढ़ाने पर व्यय की जाएगी। प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत आयुर्वेदिक दवा निर्माताओं की औषधियों की गुणवता जांचने के लिए दवा निरीक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी इस अतिरिक्त वित्तीय सहायता में राशि का प्रावधान रखा गया है।

आयुर्वेद मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए 7.58 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना का प्रस्ताव आयुष मंत्रालय को भेजा था। आयुष मंत्रालय ने राज्य द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा व्यय विवरण के आधार पर राज्य के लिये यह राशि प्रदान की है। राज्य में आयुर्वेद क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर प्रदेश को अनुपूरक कार्य योजना तैयार करने का अवसर प्राप्त हुआ। विभाग ने 19.85 करोड़ रुपये की अनुपूरक वार्षिक कार्य योजना चालू वित्त वर्ष के लिए आयुष मंत्रालय को प्रस्तुत की थी, और आयुष मंत्रालय ने 28 नवम्बर 2018 को दिल्ली में आयोजित बैठक में राज्य के लिए यह राशि स्वीकृत करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है।

विपिन सिंह परमार ने बताया कि राज्य को इतनी बड़ी राशि पहली बार प्राप्त हुई है जिससे आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। इस राशि में से 8 करोड़ रुपये आयुर्वेदिक औषधियों की खरीद पर व्यय किए जाएंगे जो राज्य के औषधि क्रय बजट के अतिरिक्त होगी। शेष राशि को अस्पतालों में आधारित संरचना उपलब्ध करवाने के लिए व्यय किया जाएगा जिसके अंतर्गत आवश्यक उपकरणों की खरीद, पंचकर्म एवं क्षारसूत्र केन्द्रों की स्थापना सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का सृजन किया जाएगा।

परमार ने बताया कि राज्य में लगभग 250 किस्म के औषधीय पौधों की खेती की जा सकती है। प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है। किसानों और बागवानों को औषधीय पौधों की खेती के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे न केवल उनकी आर्थिकी मजबूत होगी, बल्कि आयुर्वेद औषधियां तैयार करने के लिये इन पौधों की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।

राज्य की सभी पीएचसी व एचएससी को 2022 तक वैलनेस केन्द बनाने का लक्ष्य

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को वर्ष 2022 तक चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य वैलनेस केन्द्रों में स्तरोन्नत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चालू वित्त वर्ष के अंत तक 132 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को वैलनेस केन्द्र बनाया जाएगा। यह बात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद मंत्री विपिन सिंह परमार ने आयुष्मान भारत के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 'हैल्थ व वैलनेस सेंटर' को क्रियान्वित करने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय अभिविन्यास कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कही।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत बहुत ही महत्वकांक्षी योजना है जिसमें व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना दो मुख्य स्तम्भ हैं। दोनों स्तम्भ एक साथ मिलकर 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज' के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वरदान सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में वैलनेस केन्द्रों की स्थापना के दूरगामी परिणाम होंगे और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है और गैर-संक्रमणीय बीमारियों सहित अनेक बीमरियों की प्राथमिक और माध्यमिक रोकथाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बहुत कम लागत पर विकृति और मृत्युदर को कम करती है साथ ही द्वितीयक और तृतीयक देखभाल की आवश्यकता को भी कम करती है।

विपिन सिंह परमार ने कहा कि देश के सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले, स्वास्थ्य सुरक्षा मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाकर देश के 50 करोड़ लोगों को नि:शुल्क स्वास्थ्य कवच का बड़ा तोहफा प्रदान किया है, जो विकसित होते भारत की जरूरत भी था। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से हिमाचल प्रदेश के 21 लाख से अधिक लोग पांच लाख रूपये तक के स्वास्थ्य बीमा कवच के दायरे में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना से वंचित लोगों के लिए राज्य में 'हिम केयर' योजना शुरू की गई है और इसकी सभी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि योजनाएं तभी सार्थक होंगी यदि वे धरातल तक पहुंचे और अंतिम छोर में व्यक्ति को लाभान्वित करें। इसमें चिकित्सकों की भूमिका अह्म है और उन्हें मिशन के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग भगवान के बाद डाक्टर को जीवन रक्षक मानते हैं और यह विश्वसनीयत बनाए रखने के लिए समर्पण की भावना के साथ मानव सेवा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता, यदि ईमानदार और कर्मठ प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यपालक को इस बात पर गौर करना चाहिए कि समाज का दृष्टिकोण उनके प्रति क्या है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर निष्पादन के लिए चार पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में आ रहे बदलाव के साक्षी हैं। उन्होंने इसके लिए चिकित्सकों तथा पैरा मेडिक्स को बधाई देते हुए कहा कि अभी लक्ष्यों को हासिल करना शेष है।

विपिन सिंह परमार ने कहा कि चम्बा जिले के समोट तथा सुंडला में वैलनेस केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी हैं और राज्यभर में इस योजना को शीघ्र पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी माह 14 और 17 तारीख को मेडिकल कॉलेज टांडा तथा आईजीएमसी शिमला में चिकित्सकों के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किए गए हैं तथा सोलन में भी यह साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है। राज्य में डाक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी और वैलनेस केन्द्रों के संचालन को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि लगभग 350 चिकित्सकों को इन साक्षात्कार के माध्यम से भरा जा रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रदेश में न केवल डाक्टरों की कमी पूरी होगी बल्कि सरपल्स हो जाएंगे।

भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र की कार्यकारी निदेशक डा. रजनी वैद्य ने वैलनेस केन्द्रों के क्रियान्वयन पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि वैलनेस केन्द्रों की अवधारणा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कम उपयोगिता, जिला अस्पतालों तथा मेडिकल कालेजों पर अत्यधिक बोझ व दबाव की समस्या का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि यह अवधारणा उपचार की लागत को कम करेगी। उन्होंने वैलनेस केन्द्रों में योग को उपयुक्त स्थान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्हेंने कहा कि केन्द्रों के सुचारू व बेहतर संचालन के लिए चिकित्सकों सहित सभी पैरा मेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर्ज को प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है।

डा. रजनी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं और राज्य में टैलीमेडिसिन जैसी अत्याधुनिक उपचार प्रणाली आरंभ करना सराहनीय कदम है। उन्होंने वैलनेस केन्द्रों की औपचारिकताओं, आवश्यकताओं व संचालन के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की।

विशेष सचिव स्वास्थ्य निपुण जिंदल ने कहा कि स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पहुंच तथा इन्हें वहन करने की सुविधा सभी लोगों तक सुनिश्चित बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गुणात्मक स्वास्थ्य उपचार पर विशेष बल दिया गया है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध ढंग से बुनियादी सुविधाओं, अधोसरंचना तथा उपकरणों व स्टॉफ की समुचित व्यवस्था प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने दिया प्रधानमंत्री को धर्मशाला आने का न्योता

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की तथा उन्हें वर्तमान प्रदेश सरकार का सत्ता में एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर 27 दिसम्बर को धर्मशाला आने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा तथा उन्होंने प्रधानमंत्री से इस अवसर पर आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने का आग्रह किया।

उन्होंने प्रधानमंत्री से सतलुज जल विद्युत निगम को भारत सरकार के संयुक्त उपक्रम का दर्जा यथावत बनाए रखने तथा प्रदेश व इसके लोगों के हित में राज्य सरकार के हिस्से को बनाए रखने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने 27 दिसम्बर को धर्मशाला आने की सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।

पिछली राज्य सरकार ने विरासत में दिया 46,500 करोड़ रुपये का ऋणभार: मुख्यमन्त्री

शिमला/शैल। वर्तमान राज्य सरकार के लगभग एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है और राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया 'जन मंच' राज्य के लोगों की उनके घरों के समीप शिकायतों के समाधान में वरदान साबित हुआ है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पीटरहॉफ में एक टी.वी. चैनल द्वारा

आयोजित 'प्रोग्रेसिव हिमाचल मीट' समारोह को सम्बोधित करते हुए कही।

जय राम ठाकुर ने कहा कि जन मंच को राज्य में बड़ी सफलता मिली है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में आयोजित किए गए 74 जन मंच में 20,000 से अधिक शिकायतों को निवारण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के दौरान उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों की विकासात्मक आकांक्षाओं और जरूरतों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य के कुल 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 65 निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान उनकी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि किसानों आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास वर्ष 2022 तक किसानों को आय को दोगुना करने का है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार केन्द्र से प्रदेश के लिए 10,000 करोड़ की विकासात्मक परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में केन्द्र सरकार राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं के प्रति विचारशील है और विकासात्मक कार्यो के लिए हमेशा से ही उदार सहायता प्रदान करती रही है। उन्होंने कहा कि राज्य को पिछली राज्य सरकार से 46,500 करोड़ रुपये का ऋण भार विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अनुत्पादक व्यय को कम करके तथा प्रभावी वित्तीय प्रबन्धन से राज्य की पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है।

एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मण्डी में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का मामला केन्द्र सरकार से उठाया है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय रेल मंत्री कालका-शिमला तथा पठानकोट-जोगेन्द्रनगर की मौजूदा रेल पटरियों को सुधारने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि स्तरोन्नयन के उपरान्त इन मार्गो पर यात्रा का समय मौजूदा पांच घण्टे से तीन घण्टे तथा नौ घण्टे से क्रमश: छ: घण्टे रह जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग, पर्यटन, बिजली, कृषि आधारित उद्योगों तथा खाद्य प्रंसस्करण इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की अपार निवेश क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए अगले वर्ष जून की महीने में धर्मशाला में 'मेगा इन्वेस्टर मीट' आयोजित करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि यह न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करेगी, बल्कि राज्य के युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर भी प्रदान करेगी।

कटे-फटे होंठ वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटाने की दिशा में बड़ा कदम

जन्म से ही कटे-फटे होंठ वाले बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौटाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। एक गैर-सरकारी संगठन स्माइल ट्रेन इंडिया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय के साथ मिलकर कटे-फटे होंठ और तालू के साथ पैदा हुए बच्चों के लिए मुफ्त सर्जरी करवाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता तीन साल के लिए है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के स्वास्थ्य कार्यकर्ता इलाज से वंचित बच्चों की पहचान करेंगे और जिला नोडल अधिकारी ऐसे बच्चों को नि:शुल्क सर्जरी की सुविधा प्रदान करने के लिए स्माइल ट्रेन इंडिया के निकटतम सहयोगी अस्पताल को रैफर करेंगे। स्माइल ट्रेन कटे-फटे होंठ व तालू से ग्रसित बच्चों के लिए सर्जरी करेंगे और सर्जरी के बाद देखभाल में मदद करेगी।

स्माइल ट्रेन ने वर्ष 2000 के बाद हिमाचल प्रदेश में 1700 से अधिक नि:शुल्क सर्जरी में मदद की है। स्माइल ट्रेन व हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच हुए इस समझौते से ज्यादा से ज्यादा पीड़ित बच्चों को लाभ मिलेगा ताकि उन्हें सामान्य जीवन जीने का मौका मिल सके और उनके मनोबल में भी बढ़ौतरी हो सके।

नि:शुल्क उपचार के लिए स्माइल ट्रेन के सहयोगी अस्पतालों में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल शिमला, फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा, मांडव अस्पताल मंडी, पंचशील नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड नगरोटा शामिल हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक मनमोहन शर्मा और स्माइल ट्रेन की सामरिक परियोजनाएं, दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय निदेशक रेणु मेहता ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक मनमोहन शर्मा ने बताया कि आरबीएसके, हिमाचल प्रदेश सरकार और स्माइल ट्रेन इंडिया के बीच समझौता हुआ है ताकि कटे-फटे होंठ व तालू से ग्रसित राज्य के बच्चों को गुणात्मक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जा सके। इस समझौते के बाद मुस्कान ट्रेन के सहयोगी अस्पतालों के माध्यम से पीड़ित बच्चों को समय पर नि:शुल्क ईलाज उपलब्ध होगा और हम मिलकर ऐसे परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ला पाने में कामयाब हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह एक बड़ा कदम है।

साझेदारी पर बात करते हुए, स्माइल ट्रेन की सामरिक परियोजनाएं, दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय निदेशक रेणु मेहता ने कहा कि इस योजना और इसके ईलाज के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हम हिमाचल प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। समय पर सर्जरी एक बच्चे को जीवन जीने का दूसरा मौका देती है। हमें यकीन है कि आरबीएसके के सहयोग से हम दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम होंगे, जहां पर अभी तक गुणात्मक उपचार या सर्जरी उपलब्ध नहीं है। संस्था ने हिमाचल प्रदेश में अब तक 1700 से अधिक सर्जरी प्रदान करने में मदद की है और यह साझेदारी हमें हमारी पहुंच बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा नि:शुल्क सर्जरी उपलब्ध करवाने में मदद करेगी।

सड़कों के निर्माण को 843.72 करोड़ स्वीकृत करने पर केन्द्र सरकार का धन्यवाद

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य के लिए 219 ग्रामीण सड़कों तथा 9 पुलों के निर्माण के लिए 843.72 करोड़ की राशि स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार तथा केन्द्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर का धन्यवाद किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत राज्य में 1394 किलोमीटर सड़कें व 466 मीटर की कुल लम्बाई के 9 पुलों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उदारता के कारण राज्य सरकार प्रदेश के लिए लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं स्वीकृत करवाने में सफल रही है।

वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 85000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने की कवायद

हिमाचल प्रदेश सरकार कांगड़ा के धर्मशाला में जून, 2019 में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन 85000 करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत है। साथ ही, राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के पर भी सरकार की नजर है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक विस्तृत योजना को मंजूरी दे दी गई है। ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षण केन्द्र और एचपीसीए स्टेडियम में किया जाएगा।

धर्मशाला में मुख्य कार्यक्रम के अलावा, देश के प्रमुख व्यापार केंद्रों में छः राष्ट्रीय रोड़ शो के साथ-साथ राज्य के भीतर तीन अंतर्राष्ट्रीय रोड़ शो और पांच मिनी कॉन्क्लेव मुख्य आयोजन से पहले आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली में राजदूतों का गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय भागीदारों के परामर्श से सटीक कार्यक्रमों, स्थानों तिथियां और इन कार्यक्रमों की संख्या का निर्णय लिया जाएगा।

सभी निवेश योग्य प्रस्तावों को मुख्य रूप से 8 व्यापक क्षेत्रों में शामिल करने की कार्यनीति तैयार की गई है, जिसमें कृषि-व्यवसाय क्षेत्र, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन सहित खाद्य प्रसंस्करण और फार्मा सहित उद्योग, पर्यावरण और आतिथ्य क्षेत्र सहित पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल और आयुष सहित आयुर्वेद, बुनियादी ढांचे, परिवहन सहित लोक निर्माण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कौशल विकास और शिक्षा और शहरी विकास आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र शामिल होंगे।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि वैश्विक निवेशकों की बैठक किसी एक विभाग तक ही सीमित नहीं है, लेकिन सभी विभागों की बैठक को सफल बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक भूमिका है। इसलिए विभागों को अपनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भूमिका निर्धारित करना और इसे व्यवहारिक बनाना होगा और कार्यक्रम में योगदान के लिए विशेष रूप से उल्लिखित आठ क्षेत्रों में अपने दायित्वों को समझना होगा। उन्होंने यह भी जोर दिया कि आठ क्षेत्रों में राज्य में संभावित निवेश के सभी मार्गों का विभाजन केवल व्यापक और सामान्य है और उसमें बदलाव या परिवर्तन की जरूरत है जिसकी निष्पादन सह निगरानी समिति समय-समय पर समीक्षा करेगी।

मंत्री ने सभी विभागों से कहा है कि वे अपनी विशिष्ट और समयबद्ध कार्य योजना तैयार करें और इसमें आवश्यक सुधार करें जो कि राज्य में निवेश की सुविधा के लिए और राज्य में व्यवसाय करने में और आसानी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में करने आवश्यक हैं।

निवेशकों को ऐसी परियोजनाओं के लिए सरकारी या निजी भूमि की उपलब्धता के बारे में निवेश योग्य परियोजनाओं की सूची तैयार करने और जानकारी के अलावा संभावित निवेश के लिए उप क्षेत्रों की पहचान के लिए कहा गया है। ऐसी परियोजनाओं के लिए नियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया और प्रणाली का सरलीकरण किया जाएगा। यदि विभागों ने पहले से ही ऐसी कुछ परियोजनाओं की पहचान की है, तो उन्हें ऐसी परियोजनाओं के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव लाना होगा। सभी विभागों को अपने क्षेत्रों में निवेश की सुविधा के लिए और संभावित उद्यमियों के लिए उन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए अपनी योजनाओं और प्रोत्साहनों की समीक्षा करनी होगी। धारा 118 के तहत परियोजनाओं में निवेश के लिए भूमि पट्टे के लिए अनुमति देने के लिए आवेदन संशोधित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश काश्तकार व भू-सुधार अधिनियम, 1972 पर तेजी से कार्यवाही की जाएगी और अनावश्यक प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा। राजस्व विभाग को अधिक सुविधा, पारदर्शिता और बेहतर निगरानी के लिए प्रक्रिया को ऑनलाइन करने को कहा गया है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार के लिए एक अलग नीति तैयार की जाएगी। एकल खिड़की प्रणाली के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति मांगने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।

सभी क्षेत्रों और विभागों के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन वेब पोर्टल मंच तैयार किया जाएगा। इन्वेस्ट इण्डिया और अन्य राज्यों की व्यवस्था के आधार पर राज्य स्तरीय निवेश संवर्धन एजेंसी के सृजन का भी प्रस्ताव है।

निविदा आमंत्रित करने और एमओयू को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया सभी विभागों द्वारा तुरंत शुरू की जाएगी। उन्हें 10-11 जून, 2019 के धर्मशाला में एमओयू में प्रवेश करने या संभावित निवेशकों को परियोजनाएं देने के लिए मुख्य कार्यक्रम की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, बल्कि सभी एमओयू और अन्य उद्यम जो संभावित उद्यमियों के साथ होने हैं, इन्हें विभिन्न क्षेत्रों और विभागों को दिए गए लक्ष्यों की उपलब्धियों में गिना जाएगा।

कर्ज माफी है सत्ता की चाबी

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करने की बजाए उन्हें कर्ज देने की बात करते हैं। जब ये राजनैतिक दल किसानों को इस कर्ज को लौटाने का सक्षम बनने की सोच देने के बजाए उसे माफ करके मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो स्पष्ट है कि ऐसा करके वे ना तो किसानों का सोचते हैं ना देश का। बल्कि वो इस प्रकार का लालच देकर किसानों को सत्ता तक पहुंचने का एक जरिया मात्र समझते हैं। सत्तासुख के लिए ये राजनैतिक दल देश की अर्थव्यवस्था और उसके भविष्य को भी ताक पर रख देते हैं।

''डॉ. नीलम महेन्द्र''

तीन राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजों के परिणामस्वरूप कांग्रेस की सरकार क्या बनी, न सिर्फ एक मृतप्राय अवस्था में पहुंच चुकी पार्टी को संजीवनी मिल गई, बल्कि भविष्य की जीत का मंत्र भी मिल गया। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने इरादे स्पष्ट कर चुके हैं कि किसानों की कर्जमाफी के रूप में उन्हें जो सत्ता की चाबी हाथ लगी है उसे वो किसी भी कीमत पर अब छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो राज्यों के मुख्यमंत्रियो ने शपथ लेने के कुछ घंटों के भीतर ही चुनावों के दौरान कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों के कर्जमाफ करने के राहुल गांधी के वादे को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। एक प्रकार से कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2019 के चुनावी रण में उसका हथियार बदलने वाला नहीं है। लेकिन साथ ही कांग्रेस को अन्दर ही अंदर यह भी एहसास है कि इसका क्रियान्वयन आसान नहीं है। क्योंकि वो इतनी नासमझ भी नहीं है कि यह न समझ सके कि जब किसी भी प्रदेश में कर्जमाफी की घोषणा से उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो जब पूरे देश में कर्जमाफी की बात होगी तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। मध्यप्रदेश को ही लें, कर्जमाफी की घोषणा के साथ ही मध्यप्रदेश की जनता पर 34 से 38 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आ जाएगा।

पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा है कि कर्जमाफी जैसे कदमों से देश को राजस्व का बहुत नुकसान होता है और इस प्रकार के फैसले देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि इन घोषणाओं का फायदा केवल सांठ गांठ वालों को ही मिलता है, गरीब किसानों को नहीं। उनके इस कथन का समर्थन कैग की वो रिपोर्ट भी करती है जो कहती है कि 2008 में कांग्रेस जिस कर्जमाफी के वादे के साथ सत्ता में आई थी, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी, जिस कारण उसका फायदा किसानों को नहीं मिल पाया। इसलिए जब वो राहुल जो चुनाव नतीजों के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानते हैं कि ''कर्जमाफी किसानों की समस्या का सही समाधान नहीं है'', वो ही राहुल अब यह कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री को तब तक सोने नहीं देंगे जब तक वह किसानों का कर्जा माफ नहीं कर देते, तो उनके इस कथन से नकारात्मक राजनीति की दुर्गंध आती है। कहीं वो इन तीन प्रदेशों में कांग्रेस द्वारा किए गए कर्जमाफी का ठीकरा केंद्र के मत्थे तो नहीं मढ़ना चाहते? कुछ भी हो इस प्रकार की ब्यान बाजी से वे केवल देश की भोली भाली जनता की अज्ञानता का लाभ उठाकर अपने तत्कालिक राजनैतिक स्वार्थ को हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं न कि किसानों की समस्या को सुलझाने का लक्ष्य। समझने वाली बात यह भी है कि दरअसल जब राजनैतिक दल किसानों की कर्जमाफी की बात करते हैं, तो वे किसानों की नहीं अपनी बात कर रहे होते हैं। उनका लक्ष्य किसानों की समस्या का हल नहीं अपने वोटों की समस्या का हल होता है। उनकी मंजिल किसानों की खुशहाली सुनिश्चित करना नहीं अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करना होता है।

यह बहुत ही खेद का विषय है कि आज हर राजनैतिक दल सत्ता चाहता है लेकिन इसे हासिल करने के लिए वो देश के लोकतंत्र का भी मजाक उड़ाने से नहीं हिचकता। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को देश की खुशहाली और तरक्की का प्रतीक माना जाता था और जिस वोटर के हाथ सत्ता की चाबी होती थी, इन राजनैतिक पार्टियों की रस्साकस्सी ने उस लोकतंत्र और उसके नायक, एक आम आदमी, एक वोटर को आज केवल अपने हाथों की कठपुतली बनाकर छोड़ दिया है। क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी से आगे की सोच ही नहीं पाता, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि उसके दिन की शुरुआत पीने के लिए पानी की जुगाड़ से शुरू होती है और उसकी सांझ दो रोटी की तलाश पर ढलती है, वो देश का भला बुरा क्या समझे, क्या जाने क्या चाहे? वो किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, जो कड़ी धूप हो या बारिश, सर्द बर्फीली हवाओं का मौसम हो या लू के थपेड़े, उसके दिन की शुरुआत कड़ी मेहनत से होती है लेकिन सांझ कांदा और सूखी रोटी से होती है जो जी तोड़ मेहनत के बाद भी अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की हर कोशिश में असफल हो जाता है वो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या जाने? लेकिन देश के राजनैतिक दल जो चुनाव जीतकर देश चलाने का वादा और दावा दोनों करते हैं, वो तो देश और उसकी अर्थव्यवस्था का भला और बुरा दोनों समझते हैं! उसके बावजूद जब वे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करने की बजाए उन्हें कर्ज देने की बात करते हैं। जब ये राजनैतिक दल किसानों को इस कर्ज को लौटाने का सक्षम बनने की सोच देने के बजाए उसे माफ करके मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो स्पष्ट है कि ऐसा करके वे ना तो किसानों का सोचते हैं ना देश का। बल्कि वो इस प्रकार का लालच देकर किसानों को सत्ता तक पहुंचने का एक जरिया मात्र समझते हैं। सत्तासुख के लिए ये राजनैतिक दल देश की अर्थव्यवस्था और उसके भविष्य को भी ताक पर रख देते हैं। क्या राहुल गांधी के पास इस बात का जवाब है कि 2008 में कांग्रेस द्वारा देश भर में किसानों की कर्जमाफी के बावजूद 2018 में भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार क्यों नहीं आया? कर्जमाफी के बावजूद किसानों की आत्महत्या थम क्यों नहीं रहीं?

इसलिए बेहतर होता कि राहुल गांधी अपनी सोच का दायरा बढ़ाते, अपनी पार्टी से पहले देश का सोचते, अपने ब्यानों में परिपक्वता लाते, अब तक किसानों की नहीं, वोटों की सोच रहे थे, अब वोटों की नहीं किसानों की सोचें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की सोचें क्योंकि उनकी इस प्रकार की गैर जिम्मेदार ब्यानबाजी से ना किसानों का फायदा होगा ना देश का। बल्कि अब भाजपा भी दबाव में आ गई है शायद इसीलिए भाजपा की असम सरकार ने किसानों के 600 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है और गुजरात की भाजपा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 6 लाख उपभोक्ताओं के सभी बकाया बिजली बिल माफ करने की घोषणा कर दी है। सोचने वाली बात यह है कि इस प्रकार की जो परिपाटी शुरू हो गई है उससे देश पीछे ही जायेगा आगे नहीं। राजनैतिक दल तो इस दलसल में फंसते ही जायेंगे और अंततः देश को भी इसी दलदल में डुबो देंगे। अब भी समय है चुनाव आयोग स्थिति की गंभीरता का संज्ञान ले और चुनावों के दौरान इस प्रकार के वादों को रिश्वत देकर खरीदने की श्रेणी में लाकर गंभीर अपराध घोषित करे तथा ऐसी घोषणाओं को करने वाली पार्टी पर प्रतिबंध लगाए

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

बैंक प्रबन्धक के सहयोग से ऊना में चार लोग हुए एक शाहिद के षडयंत्र का शिकार

पुलिस ने शिकायत मिलने के बावजूद नहीं किया मामला दर्ज

शिमला/शैल। कुछ शातिर लोग केन्द्र सरकार की योजनाओं का दुरूपयोग करके आम आदमीयों को अपनी जालसाजी का शिकार बना रहे हैं और इसमें बैंक प्रबन्धन भी सहयोगी बन रहा है तथा प्रशासन भी ऐसे षडयंत्र पर आखें बन्द करके बैठ गया है। इसका एक किस्सा ऊना की रक्कड़ कालोनी में सामने आया है जहां एक मोहम्मद शाहिद हुसैन और उसकी पत्नी ने केनरा बैंक प्रबन्धन के सहयोग से पांच लोगों को अपना शिकार बना लिया है। इस किस्से की हद तब हो गयी जब स्थानीय पुलिस ने इसकी शिकायत मिलने के बावजूद इस मामले में कोई केस दर्ज नही किया जबकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पुलिस को उसे मिली हर शिकायत पर एक सप्ताह के भीतर मामला दर्ज करना होता है और यदि वह ऐसा न करे तो उसे शिकायतकर्ता को इसका कारण लिखित में सूचित करना होता है। यह किस्सा क्या है और कैसे घटा यह जानने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि केन्द्र सरकार की वह योजना कौन सी है जिसके तहत यह घटा है।

केन्द्र सरकार की स्मॉल, माईक्रो और मीडियम उद्योगों को प्रोत्साहन एवम् संरक्षण देने की योजना है। यह योजना 2006 में अधिसूचित हुई थी। इसके तहत उद्योग लगाने वाले व्यक्ति को दो करोड़ ऋण लेने के लिये किसी भी तरह की धरोहर/संपत्ति को बैंक में गिरवी रखने की आवश्यकता नही थी क्योंकि इसके लिये सरकार ने एक CGTMSE(Credit Guarntee Fund trust for Micro and small Entetprises) स्थापित कर रखा था। इस योजना के तहत स्थापित यदि कोई इकाई डिफाल्टर हो जाती है तो यह ट्रस्ट ऋण देने वाले बैंक को उसकी 50/75/80/85 प्रतिशत तक भरपाई करता है। इस योजना में 7-1-2009 को संशोधन करके ट्रस्ट की जिम्मेदारी 62.50% से 65% तक कर दी गयी थी। इसके बाद 16-12-2013 को इसमें फिर संशोधन हुआ और ट्रस्ट की जिम्मेदारी 50% तक कर दी गयी। इस योजना के तहत स्थापित हो रही इकाई और उसको स्थापित करने वाले का आकलन करना और उससे पूरी तरह आश्वस्त होना यह जिम्मेदारी ऋण देने वाले बैंक प्रबन्धन की थी। अभी पिछले दिनों मोदी सरकार ने भी इसी योजना के तहत 59 मिनट में एक करोड़ का ऋण देने की घोषणा की है। यह इसी आधार पर संभव है कि ऋण लेने वाले को कुछ भी धरोहर के रूप में बैंक के पास गिरवी नही रखना है केवल बैंक प्रबन्धन को ऋण लेने वाले और उसकी योजना से आश्वस्त होना है। केन्द्र सरकार की यह एक बहुत बड़ी योजना है और इसके लिये एक पूरा मन्त्रालय स्थापित है। वीरभद्र सिंह भी इसके केन्द्र में मन्त्री रह चुके हैं। इस योजना की पूरी जानकारी आम आदमी से ज्यादा बैंको के पास है और एक तरह से उन्हें ही लोगों को इसके लिये प्रोत्साहित करना है।

जब सरकार उद्योग स्थापित करने के लिये इस तरह की सहायता का आश्वासन देगी तो यह स्वभाविक है कि कोई भी आदमी इसका लाभ उठाना चाहेगा। इसी का फायदा उठाकर मोहम्मद शाहिद हुसैन ने पांच अलग नामों से उद्योग इकाईयां स्थापित की। शाहिद हुसैन हिमाचल का निवासी नही था और यहां पर उसके पास कोई संपत्ति नही थी। इसलिये उसे यहां पर उद्योग लगाने के लिये स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी चाहिये थी। इस हिस्सेदारी को हासिल करने के लिये उसने स्थानीय लोगों से मित्रता बनानी आरम्भ कर दी और सबको अपना परिचय एक मुस्लिम बुद्धिजीवि शायर के रूप में दिया। उसकी शायरी से प्रभावित होकर कुछ लोग उसके प्रभाव में आ गये। प्रभाव में आने के बाद उसने इन लोगों को केन्द्र की इस उद्योग योजना की जानकारी देना शुरू किया। इसका विश्वास दिलाने के लिये केनरा बैंक के प्रबन्धक एस के भान से मिलाना शुरू किया। बैंक मैनेजर ने भी लोगों को इस योजना की जानकरी दी और बताया कि इसमें उन्हे ऋण लेने के लिये कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नही है। स्वभाविक है कि जब ऋण देने वाला बैंक भी ऐसी योजना की पुष्टि करेगा तब आदमी उद्योग लगाने के लिये तैयार हो ही जायेगा। उद्योग इकाईयां स्थापित कर ली यह इकाईयां आर आर वी क्रियेशनज़, रामगढ़िया इन्टरप्राईज़िज, बाला जी इन्टर प्राईज़िज, आर के इन्डस्ट्रीज और पारस होम एप्लांईसेज़ शाहिद के षडयन्त्र का असली चेहरा पासर होम एप्लॉईसैज मे सामने आया। यहां पर उसने पीयूष शर्मा को अपना हिस्सेदार बनाया। पीयूष के पिता कुलदीप शर्मा का यहां एक होटल और अपना बड़ा मकान है। शाहिद की नज़र इस संपत्ति पर आ गयी। उसने पीयूष को पार्टनर बनाकर जून 2013 में केनरा बैंक से ऋण स्वीकृत करवा लिया। फिर नवम्बर 2013 में पीयूष के पिता कुलदीन शर्मा को यह कहानी गढ़ी कि उसे 1.10 लाख यू एस डॉलर का आर्डर मिला है और इस आर्डर को पूरा करने के लिये उसे एक करोड़ के अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता है यदि कुलदीप शर्मा इस ऋण के लिये अपना मकान कुछ समय के लिये बैंक में गिरवी रखने को तैयार हो जायें तो यह आसान हो जायेगा। बेटे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वह इसके लिये तैयार हो गये। शाहिद उन्हें केनरा बैंक ले गया वहां बैंक प्रबन्धक ने भी इसकी पुष्टि कर दी और कुलदीप को मकान मारटगेज करने के लिये राजी कर लिया। 9.12.2013 को यह मारटगेज डीड साईन हो गयी। यह डीड साईन होने के बाद अन्य इकाईयों की जानकारी सामने आयी और कुलदीप के बेटे ने शाहिद के साथ अपनी पार्टनरशिप भंग कर दी। कुलदीप शर्मा ने बैंक को यह मारटगेज डीड रद्द करने के लिये लिखित में दे दिया क्योंकि इस डीड के एवज में बैंक ने कोई अतिरिक्त ऋण जारी नहीं किया था। बैंक के साथ ही कुलदीप ने संबन्धित तहसीलदार को भी सूचित कर दिया कि यह इस डीड पर अमल न करे। लेकिन तहसीलदार ने कुलदीप के आग्रह को नजरअन्दाज करके मकान बैंक के नाम लगा दिया। इस सारे किस्से की पुलिस को भी लिखित में शिकायत दे दी गयी लेकिन पुलिस ने आज तक शाहिद और बैंक प्रबन्धन के खिलाफ कोई मामला दर्ज नही किया है।

कुलदीप जैसा ही व्यवहार अन्य तीन लोगों के साथ भी हुआ है वह भी पुलिस को शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कारवाई सामने नही आयी है। अब यह भी सामने आया है कि आर के इन्डस्ट्रीज़ शाहिद की पत्नी के नाम है लेकिन यह इकाई केवल कागजों में ही कही जा रही है और इसी केनरा बैंक प्रबन्धन ने इस ईकाई के नाम पर भी कोई 50 लाख का ऋण दे रखा है। इन सारे उद्योगों को इसी बैंक से करीब दो करोड़ का ऋण दिया जा चुका है और इन उद्योगों में हिस्सेदार बनाये गये सारे स्थानीय लोग इस षडयन्त्र का शिकार हो चुके हैं। यह सारे ऋण एक ही बैंक प्रबन्धक द्वारा दिये जाना यह प्रमाणित करता है कि यह एक सुनियोजित षडयन्त्र है जिसमें बैंक प्रबन्धक की सक्रिय भूमिका रही है। अब जब पुलिस शिकायत मिलने के बाद भी मामला दर्ज नही कर रही है तब पुलिस की भूमिका भी सन्देह के घेरे में आ गयी है। इस षडयन्त्र का शिकार हुए लोगों की हताषा कब क्या गुल खिला दे इसका अनुमान लगाना कठिन है।

CGTMSE -Credit Guarantee Fund trust for Miicro and Small Enterprises

A special protection is given to the micro, small and Medium enterprises via the MSME Act, 2006. These are small scale industries which require immunity and special protection to flourish. These industries from the very backbone of our Indian Economy.One of the government- sponsored schemes for MSMEs is the CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and small Enterprises).

What is the CGTMSE?

The whole idea behind this trust i**s to provide financila assistance to these industies without any third party guarantee/ or collateral.** These schemes privide the assurance to the lenders that in case of default by them a guarantee cover will be provided by trust in the ration of 50/75/80/85 percent of the amount so given.

हिमाचल के लिये 5000 करोड़ की और परियोजनायें पाइपलाईन में, नड्डा ने किया ऐलान

शिमला/शैल। शिमला संसदीय हलके के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से प्रदेश को पिछले चार सालों में अरबों खरबों की सौगातें दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार को एक साल में ही नौ हजार करोड़ रुपए की परियोजनायें मंजूर की गई है। इसके अलावा पांच हजार करोड़ की योजनाएं अभी केंद्र सरकार के पास पाइपलाईन में हैं व इन्हें भी जल्दी ही मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल खोल कर प्रदेश को वित्तीय मदद दी है व ये आगे भी जारी रहेगी।

उन्होंने कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया और तंज कसा कि कांग्रेस के बारे में क्या कहना, उनके पास न नीति है,न नियत है और न ही नेता हैं। कांग्रेस का खेल खत्म हो चुका है। नड्डा ने कहा कि पन्ना प्रमुखों पर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य पन्ना प्रमुख अवधारणा को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख वो लोग हैं जो देश की राजनीति को दिशा देने की क्षमता रखते है।

नड्डा की तरह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा व कहा कि कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में प्रश्न किया कि एक साल में पैसा कितना आया। सरकार ने जवाब दिया कि दस हजार करोड़ की परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। लेकिन वह नहीं मानें बार- बार पूछते रहे। कांग्रेस के लोगों को आदत पड़ी हुई है जब तक पैसा जेब में नहीं आ जाता तब तक वह आया नहीं मानते। हमने कहा कि माफ करना ये पैसा आपकी जेब में नहीं जाएगा। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार की एक साल की उपलब्धियों को गिनाया व कहा कि वह सबके साथ मिलजुल कर काम करेंगे।

जय राम ने कहा कि कांग्रेस के पास केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और कांग्रेस के नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए मनगढ़ंत और झूठे बयान जारी कर प्रदेश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने आचरण और चरित्र में बुनियादी शालीनता बनाए रखने में पूरी तरह असफल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम ने राजनीतिक विरोधियों की रातों की नींद हराम कर दी है। अनेक कांग्रेसी नेता भी अपनी समस्याओं व मामलों के समयबद्ध निवारण के लिए भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में जन मंच के तहत आम लोगों की 20,000 से अधिक समस्याओं और शिकायतों का निवारण किया गया है।

सम्मेलन को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भी संबोधित किया। सत्ती ने धर्मशाला में सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर आयोजित की जा रही आभार रैली में तमाम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस रैली में प्रधनमंत्री मोदी आएंगे व यह ऐतिहासिक रैली होंगी।

शिमला संसदीय हलके के सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि उन्होंने पवित्र पावंटा साहिब शहर को यमुना नगर से रेलमार्ग से जोड़ने का मामला संसद में उठाया व एमएलपीएलएडी निधि से अपने संसदीय क्षेत्र में 22.5 करोड़ रुपए व्यय किए।

पार्टी ने दावा किया कि सम्मेलन में शिमला संसदीय क्षेत्र के 2006 बूथों के 30,000 से अधिक पन्ना प्रमुखों ने भाग लिया।

हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में तीन राज्यों में सता खोने के बाद भारतीय जनता पार्टी के इस सम्मेलन में आवो-हवा बदली नजर आई। मंडी की तरह किसी भी नेता ने मौजूदा सांसद वीरेंद्र कश्यप ही लोकसभा चुनावों में भाजपा की ओर से प्रत्याशी होंगे, इस बावत एलान नहीं किया। किसी ने इशारों -इशारों में भी कुछ नहीं कहा। याद रहे कि मंडी संसदीय हलके के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह राम स्वरूप शर्मा को लोकसभा चुनावों में जिताने का आह्वान कर गए थे। लेकिन सोलन में इस बावत सब मौन रहे। जबकि वीरेंद्र कश्यप इस तरह का एलान कराने की जुगत एक अरसे से कर रहे थे। साफ है कि आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा की ओर से वही चुनाव मैदान में होंगे या कोई और चेहरा उतारा जाएगा, इसकी संभावना बनी हुई है। भाजपा सचिव हीरानंद कश्यप अपनी दावेदारी पहले ही जता चुके हैं।

याद रहे पहले इस सम्मेलन में राष्टीयकृय अध्यक्ष अमित शाह को आना था। लेकिन तीन राज्यों में सत्ता के उखड़ जाने के बाद उन्होंने इंकार कर दिया। इसके बाद केंद्रीय भूतल व सड़क मंत्री नितिन गडकरी को मनाने की कोशिश की गई वह भी नहीं आए। आखिर में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से ही काम चलाना पड़ा। नड्डा मंडी संसदीय हलके के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में नहीं आए थे।